Machine Translated by Google

2023 आईएनएससी 704

समाचार-योग्य

भारत के सर्वोच्च न्यायालय में

सिविल अपीलीय/मूल क्षेत्राधिकार

सिविल अपील सं. 2023 का 5068 (विशेष अनुमति याचिका (सी) संख्या 20743 2021 से उत्पन्न)

DEVESH SHARMA ...अपीलार्थी

बनाम

भारत संघ और अन्य। ...प्रतिवादी

साथ

सिविल अपील संख्या(एस).5122 ऑफ़ 2023 (विशेष अनुमति याचिका (सी) संख्या(एस).17633 ऑफ़ 2023 से उत्पन्न)
@D.NO.21388 OF 2022

साथ

सिविल अपील सं. 5070 ऑफ़ 2023 (विशेष अनुमति याचिका (सी) संख्या 2069 ऑफ़ 2022 से उत्पन्न)

साथ

सिविल अपील सं. 2023 का 5086 (विशेष अनुमति याचिका (सी) संख्या (एस).17630 ऑफ 2023 से उत्पन्न)
@D.NO.5464 OF 2022

साथ

2023 की सिविल अपील संख्या 5121

Machine Translated by Google

(विशेष अनुमति याचिका (सी) संख्या(एस).17632 ऑफ 2023 से उत्पन्न)

@D.NO.12813 OF 2022

साथ

सिविल अपील सं. 5069 ऑफ़ 2023 (विशेष अनुमति याचिका

(सी) संख्या 2061 ऑफ़ 2022 से उत्पन्न)

साथ

सिविल अपील संख्या (एस).5071-5084 ऑफ़ 2023 (विशेष अनुमति याचिका

(सी) संख्या 2578-2591 ऑफ़ 2022 से उत्पन्न)

साथ

सिविल अपील सं. 2023 का 5085 (विशेष अनुमति याचिका

(सी) संख्या 2022 का 3222 से उत्पन्न)

साथ

सिविल अपील सं. 2023 का 5087 (विशेष अनुमति याचिका (सी)

संख्या (एस) से उत्पन्न। 2023 का 17631)

@D.NO.7368 OF 2022

साथ

सिविल अपील सं. 2023 का 5088-5120 (विशेष अनुमति याचिका (सी)

क्रमांक 15118-15150 ऑफ 2022 से उत्पन्न)

साथ

सिविल अपील सं. 2023 का 5125 (विशेष अनुमति याचिका

(सी) संख्या 22923 2022 से उत्पन्न)

साथ

2023 की सिविल अपील संख्या 5123-5124/2023 (विशेष अनुमति याचिका (सी) 2022

की संख्या 21308-21309 से उत्पन्न)

Machine Translated by Google

साथ

रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 137 दिनांक 2022

साथ

रिट याचिका (सिविल) संख्या 881 2022

साथ

रिट याचिका (सिविल) संख्या 355 दिनांक 2022

प्रलय

SUDHANSHU DHULIA, J.

छुट्टी दी गई.

2. राजस्थान उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ का निर्णय, दिनांक

25.11.2021, इस न्यायालय के समक्ष चुनौती के अधीन है। इसके अलावा

अपील, इस न्यायालय के समक्ष तीन रिट याचिकाएँ भी हैं,

इसी मुद्दे पर. फिर भी, इन मामलों से निपटते समय,

तथ्यों के लिए, हम सिविल अपील @ एसएलपी (सी) का उल्लेख करेंगे

2021 का नंबर 20743 देवेश शर्मा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, जो

उच्च द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.11.2021 से उत्पन्न हुआ है

2021 की डीबी सिविल रिट याचिका संख्या 2109 में कोर्ट।

3. इस न्यायालय के समक्ष विवाद के मूल में क्या है

अधिसूचना दिनांक 28.06.2018, राष्ट्रीय परिषद द्वारा जारी की गई

शिक्षक शिक्षा (इसके बाद 'एनसीटीई'), इसके अभ्यास में बनाया गया

शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 23(1) के तहत शक्तियां

Machine Translated by Google

(इसके बाद इसे 'अधिनियम' के रूप में जाना जाएगा)। इस अधिसूचना से बी.एड.

डिग्री धारक प्राथमिक पद पर नियुक्ति के लिए पात्र हैं

स्कूल शिक्षक (कक्षा I से V)। सब कुछ वैसा ही, इसके बावजूद

उपरोक्त अधिसूचना, जब माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राज्य

राजस्थान सरकार ने 11.01.2021 को एक विज्ञापन जारी किया

राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा (आरटीईटी लेवल-1) को इसमें शामिल नहीं किया गया

बिस्तर। पात्र उम्मीदवारों की सूची से डिग्री धारक। यह

के समक्ष राजस्थान सरकार की कार्रवाई को चुनौती दी गई

उच्च न्यायालय। याचिकाकर्ता श्री देवेश शर्मा ने बी.एड.

डिग्री, और अधिसूचना दिनांक 28.06.2018 के अनुसार, वह था

पात्र, कई अन्य समान उम्मीदवारों की तरह। नतीजतन, वह

अन्य बातों के अलावा , राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष अपनी याचिका दायर की ।

प्रार्थना है कि विज्ञापन दिनांक 11.01.2021 को रद्द कर दिया जाए

द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 28.06.2018 का उल्लंघन था

एनसीटीई.

4. याचिकाकर्ताओं के उपरोक्त बैच के अलावा, एक और भी था

याचिकाकर्ताओं का समूह, अपनी-अपनी शिकायत के साथ। ये हैं

वे उम्मीदवार जो प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा धारक हैं

(D.El.Ed.)1 , जिसके लिए आवश्यक एकमात्र शिक्षण योग्यता थी

प्राथमिक स्तर के शिक्षक, और जो समावेशन से व्यथित हैं

---

1 संभव है कि इस डिप्लोमा को अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग नामों से पुकारा जाता हो। यही कारण है कि कहीं-कहीं इसे प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा मात्र कहा जा सकता है।

Machine Translated by Google

बी.एड. की. योग्य उम्मीदवार. उन्होंने भी पहले रिट याचिकाएं दायर की थीं
की वैधानिकता को राजस्थान उच्च न्यायालय में चुनौती
अधिसूचना दिनांक 28.06.2018. राजस्थान राज्य
उम्मीदवारों के इन दूसरे बैच का स्पष्ट रूप से समर्थन किया गया
उच्च न्यायालय के समक्ष, जैसा कि वे इस न्यायालय के समक्ष करेंगे।

5. हमारे समक्ष तीन रिट याचिकाओं में से दो (डब्ल्यूपी संख्या 137)
2022 और 881 ऑफ 2022) दिनांकित अधिसूचना को चुनौती दे रहे हैं
28.06.2018 और उसके बाद की अधिसूचनाएँ जारी की गईं
बिहार और यूपी सरकार क्रमश: आवेदन मांग रही है
बी.एड सहित पात्र उम्मीदवारों से। 2022 का WP नंबर 355
दिनांक 28.06.2018 की अधिसूचना को पुनः चुनौती दी। एसएलपी (सी) संख्या
2022 का 22923 कलकत्ता उच्च के अंतरिम आदेश के विरुद्ध है
न्यायालय ने उन याचिकाकर्ताओं को राहत देने से इनकार कर दिया जो मांग कर रहे थे
दिनांक 28.06.2018 की अधिसूचना पर रोक।

6. इसलिए इन मामलों में उत्तर दिए जाने वाले कानून का प्रश्न है
क्या एनसीटीई बीएड को शामिल करने में सही थी? एक के रूप में योग्यता
पद पर नियुक्ति के लिए समकक्ष एवं आवश्यक योग्यता
प्राथमिक विद्यालय शिक्षक (स्तर-1) की? राजस्थान उच्च न्यायालय में
आक्षेपित निर्णय ने दिनांकित अधिसूचना को रद्द कर दिया है
28.06.2018, बी.एड. धारक। के लिए अभ्यर्थियों का अयोग्य होना
प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के पद (स्तर-1).

Machine Translated by Google

7. याचिकाकर्ताओं की ओर से, हमने विद्वान वरिष्ठ को सुना है

वकील, श्री परमजीत सिंह पटवालिया जिन्होंने हमला किया है

राजस्थान हाई कोर्ट का फैसला. श्री पटवालिया उपस्थित हुए

बी.एड. के लिए योग्य उम्मीदवार और समर्थन करेंगे

अधिसूचना दिनांक 28.06.2018, और याचिकाकर्ताओं के पास था

अपने निष्कासन को राजस्थान उच्च न्यायालय में चुनौती दी। एमएस।

वरिष्ठ वकील मीनाक्षी अरोड़ा की भी बात सुनी गई

अपीलकर्ता विद्वान वकील तर्क देंगे कि उच्च न्यायालय

यह विचार करने में विफल रहा कि अधिसूचना दिनांक 28.06.2018 एक थी

केंद्र सरकार के बाद एनसीटीई ने लिया नीतिगत फैसला

की धारा 29 के तहत इस संबंध में निर्देश जारी किये थे

एनसीटीई एक्ट और हाईकोर्ट का इसमें हस्तक्षेप करना गलत था

केंद्र सरकार का नीतिगत निर्णय. एनसीटीई मोटे तौर पर

श्री द्वारा दिए गए निवेदनों से सहमत हूं

पटवालिया, और सुश्री अरोड़ा, आक्षेपित पर हमला करते हुए

निर्णय.

8. हमने विद्वान वरिष्ठ की दलीलें भी सुनी हैं

वकील श्री कपिल सिब्बल और डॉ. मनीष सिंघवी जो उपस्थित हुए

डिप्लोमा धारकों और राजस्थान राज्य क्रमशः जो

अन्य बातों के साथ-साथ यह तर्क दिया जाएगा कि एनसीटीई एक विशेषज्ञ निकाय है

के आधार पर इस मामले में स्वतंत्र निर्णय लेना

Machine Translated by Google

वस्तुनिष्ठ वास्तविकताएँ। भले ही एनसीटीई के निर्देशों का पालन करना पड़े

केंद्र सरकार, एनसीटीई को यह प्रदर्शित करना होगा

निर्देशों पर उनके द्वारा स्वतंत्र रूप से विचार किया गया था और नहीं

यांत्रिक तरीके से कार्यान्वित किया गया।

9. भारतीय संघ की ओर से हमने सीखा है

अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल सुश्री ऐश्वर्या भाटी और श्री.

विक्रमजीत बनर्जी. वे तर्क देंगे कि आक्षेपित

केंद्र की शक्तियों को नजरअंदाज कर फैसला सुनाया गया है

सरकार ने एक्ट और एनसीटीई एक्ट दोनों के तहत दिया।

इसके अलावा एक आपत्ति यह भी उठाई गई है कि संघ की ओर से

इससे पहले की कार्यवाही में भारत को एक पक्ष तक नहीं बनाया गया था

राजस्थान हाई कोर्ट!

10. सुनवाई के दौरान, इस न्यायालय ने एक पारित किया था

आदेश दिनांक 24.08.2022, बोर्ड को स्वतंत्रता प्रदान करते हुए

विभिन्न राज्यों और अन्य हितधारकों के लिए माध्यमिक शिक्षा

हस्तक्षेपकर्ता के रूप में शामिल किया जाए। इस आदेश के अनुसरण में, अनेक

अंतरिम आवेदन दायर किए गए थे जिन पर सुनवाई चल रही है

इन अपीलों के साथ.

11. “भारतीय संविधान सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण एक सामाजिक संविधान है

दस्तावेज़", ग्रानविले ऑस्टिन2 लिखता है · में निहित अधिकार

2 ऑस्टिन, ग्रानविले। "संविधान की अंतरात्मा"। भारतीय संविधान, राष्ट्र की आधारशिला, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 2000, पृष्ठ 50

Machine Translated by Google

भाग III और राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में निहित है

भाग IV एक साथ ऐसी स्थितियाँ स्थापित करता है जो लक्ष्य को आगे बढ़ाती हैं

यह सामाजिक क्रांति3 · ऑस्टिन भाग III और भाग IV कहते हैं

संविधान को "संविधान की अंतरात्मा"4 के रूप में । मुक्त

और बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा सामाजिक का एक हिस्सा थी

हमारे संविधान निर्माताओं का दृष्टिकोण।

12. बच्चों के लिए प्रारंभिक शिक्षा आज मौलिक है

संविधान के भाग III के अनुच्छेद 21ए के तहत अधिकार निहित है

भारत की। प्रत्येक बच्चे (14 वर्ष की आयु तक) में एक मौलिक गुण होते हैं

'मुफ़्त' और 'अनिवार्य' प्रारंभिक शिक्षा पाने का अधिकार। लेकिन

फिर 'मुफ़्त' और 'अनिवार्य' प्रारंभिक शिक्षा किसी काम की नहीं

जब तक कि यह एक 'सार्थक' शिक्षा भी न हो। दूसरे शब्दों में,

प्रारंभिक शिक्षा अच्छी 'गुणवत्ता' वाली होनी चाहिए, न कि केवल एक

अनुष्ठान या औपचारिकता!

13. इस संवैधानिक लक्ष्य को प्राप्त करने में हमारी प्रगति रही है

धीमा। कुछ मायनों में, यह अभी भी प्रगति पर है। से पहले

संवैधानिक 86वाँ संशोधन, शिक्षा का अधिकार था

संविधान का भाग-IV (अनुच्छेद 45), निदेशक सिद्धांत के रूप में

राज्य की नीति. जैसा कि हम जानते हैं, निदेशक सिद्धांत लक्ष्यों का एक समूह हैं

जिसे प्राप्त करने के लिए राज्य को प्रयास करना चाहिए। अनुच्छेद में निर्धारित लक्ष्य

---

3 वही – पृ. 50.

4 वही – पृ. 50.

Machine Translated by Google

संविधान का 455 (जैसा कि उस समय था), बनाना था

तक के सभी बच्चों के लिए प्रारंभिक शिक्षा निःशुल्क एवं अनिवार्य

14 वर्ष की आयु, उद्घोषणा के 10 वर्ष के भीतर

संविधान। फिर भी, इसमें दस से भी अधिक समय लगेगा

इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वर्षों।

14. 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में संशोधन किया गया

1992 में निःशुल्क एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा की घोषणा की गई

तक की आयु के सभी बच्चों को 'संतोषजनक गुणवत्ता' प्रदान की जाए

चौदह साल, इससे पहले कि देश अगली सदी यानी 21वीं सदी में प्रवेश करे

शतक।

15. बाद में उन्नी में इस अदालत के मौलिक फैसले में

कृष्णन जेपी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य। (वायु

1993 एससी 2178), यह माना गया कि बच्चों में एक मौलिकता होती है

चौदह वर्ष की आयु पूरी होने तक निःशुल्क शिक्षा का अधिकार

साल।

16. वर्ष 1997 में निःशुल्क एवं अनिवार्य करने हेतु

शिक्षा एक मौलिक अधिकार, 83वाँ संविधान

एक नया सम्मिलन करने के लिए संसद में संशोधन विधेयक पेश किया गया

भारत के संविधान के भाग III में अनुच्छेद, जो होना था

---

5 संविधान का अनुच्छेद 45 जैसा कि यह 86वें संशोधन से पहले अस्तित्व में था: "बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा
का प्रावधान। - राज्य इस संविधान के प्रारंभ से दस साल की अवधि के भीतर, मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा।" चौदह वर्ष की आयु पूरी करने तक सभी बच्चों के लिए शिक्षा।"

Machine Translated by Google

अनुच्छेद 21ए. विधेयक को जांच के लिए भेजा गया था

मानव संसाधन पर संसदीय स्थायी समिति

विकास। स्थायी समिति ने न केवल स्वागत किया

संशोधन लेकिन इसके अतिरिक्त 'की गुणवत्ता' पर भी जोर दिया गया है

बुनियादी तालीम'। इसमें यही कहा गया है.

"प्रख्यात शिक्षाविदों को लगा कि विधेयक पर चुप्पी है

शिक्षा की 'गुणवत्ता' उन्होंने सुझाव दिया कि एक होना चाहिए

विधेयक में शिक्षा की 'गुणवत्ता' का संदर्भ। सचिव,

शिक्षा ने माना कि 'गुणवत्ता' पहलू भी देखना होगा.

शिक्षा का मतलब निश्चित रूप से 'गुणवत्तापूर्ण' शिक्षा और कुछ भी होना चाहिए

उससे कम को शिक्षा नहीं कहा जाना चाहिए। इसलिए

शिक्षक शिक्षा को मजबूत करने पर जोर दिया जाएगा

सामग्री, सचिव ने कहा

अंततः, संविधान (86वाँ संशोधन) अधिनियम 2002 के माध्यम से,

अनुच्छेद 21ए को भाग III में मौलिक अधिकार के रूप में शामिल किया गया था

संविधान, और 01.04.2010 से प्रभावी हुआ। लेख

संविधान का 21ए इस प्रकार है:

> "~~अनुच्छेद 21ए: राज्य छह से~~ चौदह वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा, जैसा कि राज्य कानून द्वारा निर्धारित कर सकता है।"

मानव संसाधन विकास पर संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट के 6 पैरा 13.

Machine Translated by Google

17. उपरोक्त अधिदेश को पूरा करने के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम,
2009, 20 अगस्त 2009 को संसद द्वारा पारित किया गया था
01.04.2010 से प्रभावी हो गया। का उद्देश्य एवं कारण
अधिनियम ने जोर-शोर से और स्पष्ट रूप से घोषित किया कि अधिनियम क्या हासिल करना चाहता है
न केवल 'मुफ़्त' और 'अनिवार्य' प्रारंभिक शिक्षा, बल्कि
इस शिक्षा की 'गुणवत्ता' भी उतनी ही महत्वपूर्ण होगी!
अधिनियम की प्रस्तावना में कहा गया है कि "प्रत्येक बच्चे को यह अधिकार है
संतोषजनक एवं पूर्णकालिक प्रारंभिक शिक्षा प्रदान की
एक औपचारिक स्कूल में न्यायसंगत 'गुणवत्ता' जो कुछ को संतुष्ट करती है
आवश्यक मानदंड और मानक"।

18. इससे पहले जब एक्ट की वैधता को चुनौती दी गई थी
कोर्ट[7] , इस न्यायालय ने इसकी वैधता को बरकरार रखते हुए इस बात पर जोर दिया
अधिनियम का उद्देश्य केवल "मुफ़्त" और "अनिवार्य" प्रदान करना नहीं था
बच्चों को शिक्षा, लेकिन उद्देश्य प्रदान करना भी था
'गुणवत्ता की शिक्षा!

"इस अधिनियम के प्रावधानों का उद्देश्य केवल इतना ही नहीं है
बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित करें , लेकिन
इसमें 'गुणवत्तापूर्ण' शिक्षा प्रदान करने की भी परिकल्पना की गई है
आवश्यक बुनियादी ढाँचा और निर्दिष्ट मानदंडों का अनुपालन और
स्कूलों में मानक।" [पैरा 8, (2012) 6 एससीसी 1 देखें]

---

[7] सोसाइटी फॉर अनएडेड प्राइवेट स्कूल्स ऑफ राजस्थान बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य में। [(2012) 6 एससीसी 1]

Machine Translated by Google

19. जैसा कि हम देख सकते हैं, इसे लाने के पीछे का उद्देश्य क्या है
अग्रणी कानून 'मुक्त' की औपचारिकता पूरी करने के लिए नहीं था
और बच्चों के लिए 'प्रारंभिक शिक्षा अनिवार्य', लेकिन बनाना
प्रारंभिक शिक्षा में गुणात्मक अंतर और उसे प्रदान करना
सार्थक तरीके से. 'ए में भर्ती होने का अधिकार' जैसे प्रावधान
पड़ोस का स्कूल'8 , 'प्रवेश से इनकार नहीं'9 और 'निषेध
शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न'10 में से कुछ हैं
अधिनियम के हृदयस्पर्शी प्रावधान।

20. अधिनियम कुछ मानदंड और मानक निर्धारित करता है
प्राथमिक विद्यालयों में इसका पालन किया जाना है, और यह इसी उद्देश्य से है
सार्थक और 'गुणवत्तापूर्ण' शिक्षा प्रदान करना। कुछ का नाम बताने के लिए
इन आवश्यकताओं में से जैसे:-

A. आवश्यक बुनियादी ढांचे की आवश्यकता।
बी. विद्यार्थी शिक्षक अनुपात जो कि 30:1 है और सी. प्रशिक्षित और
योग्य दोनों की परम आवश्यकता है
शिक्षकों की।

21. बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा हो गई
यदि हम इसकी 'गुणवत्ता' से समझौता करते हैं तो यह अर्थहीन है। हमें
सर्वोत्तम योग्य शिक्षकों की भर्ती करें। एक अच्छा शिक्षक सबसे पहले होता है
किसी स्कूल में 'गुणवत्तापूर्ण' शिक्षा का आश्वासन। पर कोई समझौता

---

8 शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 3।
9 शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 15.
10 शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 17।

Machine Translated by Google

शिक्षकों की योग्यता का आवश्यक रूप से मतलब होगा a

शिक्षा की 'गुणवत्ता' से समझौता. जैक्स बरज़ुन,

अमेरिकी शिक्षाविद् और इतिहासकार, अपने मौलिक कार्य में

'टीचर इन अमेरिका' का कहना है, ''शिक्षण कोई खोई हुई कला नहीं है, बल्कि

इसके प्रति सम्मान एक खोई हुई परंपरा है”11। हालाँकि यह टिप्पणी के लिए थी

अमेरिका में उच्च शिक्षा की स्थिति, यह भी उतना ही प्रासंगिक है

यहां हमारे देश में प्राथमिक शिक्षा के उपचार पर चर्चा की जा रही है

हमारे सामने तथ्यों से उभरता है।

22. भारत में प्रारंभिक शिक्षा दो स्तरों पर है। ए है

'प्राथमिक' स्तर यानी कक्षा I से V तक, और B वरिष्ठ प्राथमिक स्तर है

यानी, कक्षा छठी से आठवीं तक। वर्तमान में हम केवल इसके बारे में चिंतित हैं

शिक्षा का "प्राथमिक स्तर"।

23. अधिनियम की धारा 23 न केवल अत्यंत महत्वपूर्ण है

यह प्रावधान करता है कि शिक्षकों की योग्यता कौन निर्धारित करेगा

प्राथमिक विद्यालय में, लेकिन इन योग्यताओं में कौन ढील दे सकता है,

और कब तक.

इसे इस प्रकार पढ़ा जाता है:-

धारा 23. शिक्षकों की नियुक्ति हेतु योग्यता एवं सेवा शर्तें .—(1)

कोई भी व्यक्ति जिसके पास इतना न्यूनतम है

11 बरज़ुन, जैक्स। "पेशा: शिक्षक"। टीचर इन अमेरिका, लिटिल ब्राउन 7 कंपनी द्वारा अटलांटिक मंथली प्रेस के सहयोग से प्रकाशित, 1945, पृष्ठ 3-13

Machine Translated by Google

केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा प्राधिकृत शैक्षणिक प्राधिकारी द्वारा निर्धारित योग्यताएं, शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होंगी।

(2) जहां किसी राज्य में शिक्षक शिक्षा में पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण प्रदान करने वाले पर्याप्त संस्थान नहीं हैं, या उप-धारा (1) के तहत निर्धारित न्यूनतम योग्यता रखने वाले शिक्षक पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हैं,

केंद्र सरकार, यदि आवश्यक समझे, तो अधिसूचना द्वारा, शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए आवश्यक न्यूनतम योग्यता में पांच वर्ष से अधिक की अवधि के लिए छूट दे सकती है, जैसा कि उस अधिसूचना में निर्दिष्ट किया जा सकता है:

बशर्ते कि एक शिक्षक, जो इस अधिनियम के प्रारंभ में, उप-धारा (1) के तहत निर्धारित न्यूनतम योग्यता नहीं रखता है, पांच साल की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम योग्यता प्राप्त करेगा:

[परंतु यह भी कि 31 मार्च, 2015 को नियुक्त या पद पर मौजूद प्रत्येक शिक्षक, जिसके पास उप-धारा (1) के तहत निर्धारित न्यूनतम योग्यता नहीं है, को नियुक्ति की तारीख से चार साल की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम योग्यता हासिल करनी होगी। निःशुल्क और अनिवार्य बच्चों की शिक्षा का अधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2017 की शुरुआत।]

(3) शिक्षकों को देय वेतन और भत्ते, और सेवा के नियम और शर्तें ऐसी होंगी जो निर्धारित की जा सकती हैं।

Machine Translated by Google

24. जबकि धारा 23 की उपधारा (1) का प्रावधान है

जहां 'शैक्षणिक प्राधिकारी' को निर्धारित करने का अधिकार दिया गया है

प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षकों के लिए योग्यता, उपधारा (2)

धारा 23 केंद्र सरकार को छूट देने का अधिकार देती है

'शैक्षणिक प्राधिकारी' द्वारा निर्धारित न्यूनतम 'योग्यताएँ',

कुछ परिस्थितियों में और सीमित अवधि के लिए.

अधिनियम की धारा 23(1) के तहत 'शैक्षणिक प्राधिकरण' है

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई), जो

23.08.2010 को एक अधिसूचना लाई गई, जिसमें आवश्यक बातें बताई गईं

प्राथमिक और उच्चतर दोनों स्तरों पर शिक्षकों के लिए योग्यताएँ

प्राथमिक स्तर। अन्य बातों के साथ-साथ, यह अधिसूचना निम्नानुसार निर्धारित करती है:-

1. न्यूनतम योग्यताएँ: - (i) कक्षा IV

(ए) कम से कम 50% अंकों के साथ सीनियर सेकेंडरी (या इसके समकक्ष) और प्रारंभिक शिक्षा में 2 साल का डिप्लोमा (चाहे किसी भी नाम से जाना जाए)

या

एनसीटीई के अनुसार कम से कम 45% अंकों के साथ सीनियर सेकेंडरी (या इसके समकक्ष) और प्रारंभिक शिक्षा में 2 साल का डिप्लोमा (चाहे किसी भी नाम से जाना जाए)।

(मान्यता मानदंड और प्रक्रिया), विनियम 2002

या

कम से कम 50% अंकों के साथ सीनियर सेकेंडरी (या इसके समकक्ष) और 4 वर्षीय बैचलर ऑफ एलीमेंट्री एजुकेशन (बी.एल.एड.)

Machine Translated by Google

या

कम से कम 50% अंकों के साथ सीनियर सेकेंडरी (या इसके समकक्ष) और शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा (विशेष)।
शिक्षा)
और

(बी) एनसीटीई द्वारा अपने उद्देश्य के लिए बनाए गए दिशानिर्देशों के अनुसार उपयुक्त सरकार द्वारा आयोजित की जाने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) में उत्तीर्ण होना।

उपरोक्त अधिसूचना दिनांक 23.08.2010, प्रदान नहीं करती है

बिस्तर। प्राथमिक पद पर नियुक्ति हेतु योग्यता के रूप में

स्कूल शिक्षक. बाद में इस अधिसूचना में संशोधन किया गया, लेकिन बी.एड.

कभी भी शामिल नहीं किया गया था (आक्षेपित अधिसूचना दिनांक तक)।

28.06.2018), प्राथमिक के शिक्षकों के लिए एक आवश्यक योग्यता के रूप में

स्कूल अर्थात कक्षा I से V तक के लिए।

एक प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक पद के लिए एक अभ्यर्थी था

इन तीन योग्यताओं का होना।

उ. उसे उच्चतर माध्यमिक स्तर उत्तीर्ण होना चाहिए।
B. उसके पास प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा होना चाहिए

(डी.एल.एड.), चाहे उस राज्य में इसे किसी भी नाम से पुकारा जाता हो।
सी. उसके बाद उसे आयोजित की जाने वाली परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी

राज्य को शिक्षक पात्रता परीक्षा या टीईटी के नाम से जाना जाता है।

25. एनसीटीई को शैक्षणिक प्राधिकारी माना जाता है

प्रशिक्षित एवं योग्य शिक्षकों की नियुक्ति अनिवार्य है

Machine Translated by Google

प्राथमिक विद्यालयों में आवश्यकता. यही कारण है कि

प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक के लिए जो योग्यता निर्धारित की गई थी

प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा (D.El.Ed.) था, और कोई नहीं

बी.एड सहित अन्य शैक्षणिक योग्यता. इसके अलावा

शिक्षक पात्रता परीक्षा या टीईटी आगे के कौशल का परीक्षण करेगी

प्राथमिक स्तर पर छात्रों को संभालने के लिए एक उम्मीदवार।

इस बात पर जोर दिया जाना चाहिए कि शैक्षणिक दृष्टिकोण

प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक से कुछ प्रकार की आवश्यकता होती है

अद्वितीय। ये प्रारंभिक प्रारंभिक वर्ष हैं जहां एक छात्र के पास होता है

अभी-अभी कक्षा के अंदर कदम रखा है, और इसलिए इसकी आवश्यकता है

देखभाल और संवेदनशीलता के साथ संभाला। एक उम्मीदवार जिसके पास डिप्लोमा है

प्रारंभिक शिक्षा (D.El.Ed.) में छात्रों को संभालने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है

इस स्तर पर, क्योंकि वह एक शैक्षणिक पाठ्यक्रम से गुजर चुका है

विशेष रूप से इस उद्देश्य के लिए डिज़ाइन किया गया।

'शैक्षणिक प्राधिकरण' जो कि एनसीटीई है, द्वारा अधिदेशित है

सभी के लिए एक पाठ्यक्रम और मूल्यांकन प्रक्रिया स्थापित करने के लिए अधिनियम

एक 'बच्चे' का सर्वांगीण विकास, सभी भयों का ध्यान रखना और

चिंताएँ जो एक बच्चे को हो सकती हैं। अधिनियम की धारा 29 इस प्रकार है

अंतर्गत :-

29. पाठ्यचर्या और मूल्यांकन प्रक्रिया.—(1)

प्रारंभिक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम और मूल्यांकन प्रक्रिया किसके द्वारा निर्धारित की जाएगी?

Machine Translated by Google

शैक्षणिक प्राधिकारी द्वारा निर्दिष्ट किया जाना है
उपयुक्त सरकार, अधिसूचना द्वारा।

(2) शैक्षणिक प्राधिकरण, निर्धारित करते समय
पाठ्यक्रम और मूल्यांकन प्रक्रिया के अंतर्गत
उप-धारा (1), को ध्यान में रखा जाएगा
निम्नलिखित, अर्थात्:-

(ए) निहित मूल्यों के अनुरूप
संविधान;

(बी) बच्चे का सर्वांगीण विकास; (सी) बच्चे के ज्ञान का निर्माण,

क्षमता और प्रतिभा;

(डी) शारीरिक और मानसिक विकास
पूर्ण सीमा तक योग्यताएँ;

(ई) गतिविधियों, खोज और के माध्यम से सीखना
बाल मैत्रीपूर्ण और बाल केंद्रित तरीके से अन्वेषण;

(एफ) निर्देशों का माध्यम, जहाँ तक होगा
व्यावहारिक, बच्चे की मातृभाषा में हो;

(छ) बच्चे को भय, आघात आदि से मुक्त बनाना
चिंता और बच्चे को व्यक्त करने में मदद करना
स्वतंत्र रूप से विचार;

(ज) व्यापक और सतत
बच्चे की समझ का मूल्यांकन
ज्ञान और उसे लागू करने की क्षमता
जो उसी।"

जैसा कि हम पाठ्यक्रम और मूल्यांकन प्रक्रिया देख सकते हैं

जिसे स्थापित करने के लिए 'शैक्षणिक प्राधिकरण' को अनिवार्य किया गया है, उसकी आवश्यकता है

शैक्षणिक दृष्टिकोण जो सबसे अच्छा शिक्षक ही दे सकते हैं

बाल छात्रों से निपटने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है।

Machine Translated by Google

एक व्यक्ति जिसके पास बी.एड. योग्यता के लिए प्रशिक्षित किया गया है

माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर शिक्षण प्रदान करना

छात्र. उनसे प्राथमिक स्तर पर प्रशिक्षण देने की अपेक्षा नहीं की जाती है

छात्र.

डिप्लोमा के बीच अंतर की सराहना करने के लिए

प्रारंभिक शिक्षा (प्रत्येक में इसे अलग-अलग नामों से पुकारा जाता है

राज्य), और बैचलर ऑफ एजुकेशन (बी.एड.), हम अब और नहीं देखते हैं

राष्ट्रीय शिक्षक परिषद द्वारा जारी अधिसूचनाओं की तुलना में

शिक्षा (एनसीटीई) समय-समय पर स्वयं।

एनसीटीई विनियम, 2009 का परिशिष्ट 2 इस प्रकार बताता है

प्रारंभिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है? ऐसा बताया गया है

इस प्रकार है:

"1. प्रस्तावना

1.1 प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा (डी.एल.एड) शिक्षक शिक्षा का दो साल का व्यावसायिक कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य शिक्षा के प्रारंभिक चरण, यानी कक्षा I से VIII के लिए शिक्षकों को तैयार करना है। प्रारंभिक शिक्षा का उद्देश्य समुदाय की सक्रिय भागीदारी के साथ सामाजिक और लैंगिक अंतर को पाटते हुए एक समावेशी स्कूल वातावरण में सभी बच्चों की बुनियादी सीखने की जरूरतों को पूरा करना है।

1.2 प्रारंभिक शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम में बीटीसी, जेबीटी, डी.एड जैसे विभिन्न नामकरण हैं। और (शिक्षा में डिप्लोमा)। अब से, कार्यक्रम का नामकरण सभी राज्यों और उसके लिए समान होगा

Machine Translated by Google

इसे 'प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा' (D.El.Ed) के रूप में जाना जाएगा।

यही विनियम इसके परिशिष्ट 4 में B.Ed का वर्णन इस प्रकार करता है

इस प्रकार है:

"1. प्रस्तावना बैचलर
ऑफ एजुकेशन प्रोग्राम, जिसे आम तौर पर बी.एड. के रूप में जाना जाता है, एक पेशेवर पाठ्यक्रम है जो उच्च प्राथमिक या मध्य स्तर (कक्षा VI-VIII), माध्यमिक स्तर (कक्षा IX-X) और वरिष्ठ माध्यमिक स्तर के लिए शिक्षकों को तैयार करता है। (कक्षा XI-XII)। कार्यक्रम को विनियम 2 के खंड (बी) में परिभाषित अनुसार समग्र संस्थानों में पेश किया जाएगा।"

इसलिए यह स्पष्ट है कि बी.एड. पाठ्यक्रम के लिए डिज़ाइन नहीं किया गया है

प्राथमिक स्तर पर शिक्षण.

इसके अलावा, बी.एड का समावेश। प्राथमिक के लिए उम्मीदवार

वर्ग इस न्यायालय के कई निर्णयों की जद में है, इस प्रकार

कोर्ट ने लगातार उस डिप्लोमा को प्राथमिक माना है

शिक्षा (डी.एल.एड.) न कि बी.एड., में उचित योग्यता है

प्राथमिक विद्यालय।

26. दिलीप कुमार घोष एवं अन्य बनाम अध्यक्ष एवं में

अन्य[12] , इस न्यायालय को इस प्रश्न पर निर्णय लेना था कि क्या बी.एड

डिग्री प्राप्त उम्मीदवार की तुलना डिग्री धारक उम्मीदवार से की जा सकती है

प्राथमिक विद्यालय शिक्षण में प्रशिक्षण या दूसरे शब्दों में कौन है

प्राथमिक विद्यालयों के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित। का विवाद

---

12 (2005) 7 एससीसी 567

Machine Translated by Google

अपीलकर्ता (उपरोक्त मामले में) जो बी.एड थे। उम्मीदवार थे

कि, उनका पाठ्यक्रम (बी.एड.), उन्हें प्राथमिक कक्षाओं को पढ़ाने के लिए तैयार करता है।

इस न्यायालय ने उनके तर्क को खारिज कर दिया। पैरा 9 में, यह कहा गया है

निम्नानुसार:

> "बिस्तर में। बाल मनोविज्ञान जैसे विषयों का पाठ्यक्रम
> नहीं पाए जाते. दूसरी ओर, पाठ्यक्रम एक का है
> सामान्य प्रकृति और सिद्धांत जैसे विषयों से संबंधित है
> शैक्षिक-पाठ्यक्रम शैक्षिक का अध्ययन करते हैं,
> मनोविज्ञान, आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास,
> सामाजिक संगठन और शिक्षण विधियाँ, आदि।"

फिर पैरा 10 में इसे इस प्रकार कहा गया:

> “.....प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाने के लिए, इसलिए,
> किसी को बाल मनोविज्ञान और विकास के बारे में जानना चाहिए
> कम उम्र में एक बच्चा. जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है,
> अपीलार्थी उन अभ्यर्थियों को पसंद करते हैं जो बी.एड. में प्रशिक्षित हैं।
> पढ़ाने के लिए डिग्री का होना आवश्यक नहीं है
> प्राथमिक कक्षा के छात्र. वे प्रशिक्षित नहीं हैं और
> के बच्चे के मनोविज्ञान को समझने के लिए सुसज्जित
> कच्ची उम्र।"

पीएम लता और अन्य बनाम केरल राज्य और में

अन्य13 का तर्क है कि बी.एड. योग्यता अधिक है

प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा (D.El.Ed.) से अधिक योग्यता

खारिज कर दिया गया था। फिर, यह मामला सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष था

बीएड अभ्यर्थी प्राइमरी स्कूल में नियुक्ति का दावा कर रहे थे

शिक्षकों के दावे के आधार पर कि उनकी शैक्षणिक

योग्यता (अर्थात बी.एड.) डिप्लोमा से भी अधिक थी

---

13 (2003) 3 एससीसी 541

Machine Translated by Google

प्रारंभिक शिक्षा (डी.एल.एड.) जो दूसरे के पास थी

उम्मीदवार। उक्त मामले के पैरा 10 में, यह निम्नानुसार कहा गया था:

> "हमें उत्तरदाताओं द्वारा दिए गए इस तर्क में बिल्कुल भी बल नहीं मिला कि बी.एड. योग्यता टीटीसी से उच्च योग्यता है और इसलिए, बी.एड. उम्मीदवारों को पद के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए पात्र माना जाना चाहिए...

इन निष्कर्षों को सुप्रीम कोर्ट ने योगेश मामले में दोहराया था

कुमार बनाम एनसीटी सरकार, दिल्ली14 , हालांकि इसे बरकरार रखा गया

बिस्तर। फिर भी, शिक्षण के क्षेत्र में एक अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त योग्यता है

यह एक प्रशिक्षण है जो एक उम्मीदवार को उच्च कक्षाओं को पढ़ाने के लिए तैयार करता है,

प्राथमिक स्तर पर कक्षाएं नहीं।

27. बी.एड. के प्राथमिक स्तर पर शिक्षकों के लिए कोई योग्यता नहीं है

स्कूली शिक्षा. ए से आवश्यक शैक्षणिक कौशल और प्रशिक्षण

प्राथमिक स्तर पर शिक्षक से बी.एड. की अपेक्षा नहीं की जाती है। प्रशिक्षित

अध्यापक। उन्हें उच्च स्तर, पद पर कक्षाओं को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है

प्राथमिक, माध्यमिक और ऊपर. प्राथमिक स्तर यानी कक्षा I से लेकर

कक्षा V में प्रशिक्षण D.El.Ed या जिसे डिप्लोमा इन के नाम से जाना जाता है

बुनियादी तालीम। यह एक D.El.Ed है. प्रशिक्षण पाठ्यक्रम जो है

एक शिक्षक में कौशल प्रदान करने के लिए डिज़ाइन और संरचित किया गया है

प्राथमिक स्तर के छात्रों को पढ़ाएं।

---

14 (2003) 3 एससी 548

Machine Translated by Google

इसलिए, निहितार्थ से बी.एड. को शामिल किया जाना चाहिए। के तौर पर

योग्यता का अर्थ है 'गुणवत्ता' को कम करना

प्राथमिक स्तर पर शिक्षा. शिक्षा की 'गुणवत्ता' जो ऐसी थी

संपूर्ण प्रारंभिक शिक्षा का एक महत्वपूर्ण घटक

इस देश में आंदोलन, जिसकी हमने चर्चा की है

इस आदेश के पूर्ववर्ती पैराग्राफ.

28. हम इस तथ्य के प्रति भी सचेत हैं कि, अधिसूचना तक

दिनांक 28.06.2018 को एनसीटीई की सतत नीति रही

बी.एड को बाहर करें प्राइमरी की पात्रता मानदंड से उम्मीदवार

स्कूल शिक्षक. 23.08.2010 अधिसूचना में - प्रथम दिया गया

एनसीटीई द्वारा "शैक्षणिक प्राधिकारी" के रूप में अपनी क्षमता के तहत

आरटीई अधिनियम की धारा 23, जिसका उल्लेख किया गया है

पूर्ववर्ती पैराग्राफ, बी.एड. योग्य शिक्षक नहीं थे

प्राथमिक कक्षाओं के लिए विचार किया गया। फिर भी, विशुद्ध रूप से करने के लिए

विभिन्न राज्य सरकारों को पर्याप्त प्रशिक्षण स्थापित करने के लिए तैयार करना

विशेष प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कॉलेज/केंद्र

प्रारंभिक शिक्षक, बी.एड. अभ्यर्थियों को आगे भी जारी रहना था

बहुत सीमित अवधि.

29. यह वर्ष से प्रारंभ होने वाले प्रारंभिक काल के दौरान था

2010 के बाद, जब अधिनियम और एनसीटीई के बाद के आदेश

प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के लिए योग्यताएँ निर्धारित की गईं

Machine Translated by Google

देश भर में। लेकिन अनिवार्य रूप से बी.एड. योग्य शिक्षक
में शिक्षकों की पात्रता के दायरे से बाहर रखा गया
प्राथमिक विद्यालयों को बी.एड. के लिए "योग्यता" नहीं मानी गई
प्राथमिक स्तर पर शिक्षक.

बी.एड. में अंतर्निहित शैक्षणिक कमजोरी। पाठ्यक्रम (के लिए)
प्राथमिक कक्षाएँ), अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त है, और यही कारण है कि
आक्षेपित अधिसूचना में ही यह प्रावधान है कि बी.एड.
प्रशिक्षित शिक्षकों को छह माह का प्रशिक्षण लेना होगा
प्रारंभिक कक्षाएँ, उनके पहले दो वर्षों के भीतर
नियुक्ति।

इस पृष्ठभूमि में, बी.एड. का समावेश। के लिए उम्मीदवार
प्राथमिक स्तर की कक्षाएं हमारी समझ से परे हैं।

हमने अब तक देखा है कि 'गुणवत्ता' और की आवश्यकता है
विधायिका द्वारा सार्थक प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया गया
साथ ही पूरे शैक्षणिक प्राधिकारी द्वारा। प्राइमरी में
शिक्षा, शिक्षा की 'गुणवत्ता' पर किसी भी तरह का समझौता मतलब होगा
अनुच्छेद 21ए और अधिनियम के जनादेश के खिलाफ जा रहा है।
प्राथमिक शिक्षा के मूल्य को कभी भी बढ़ा-चढ़ाकर नहीं बताया जा सकता।

मायरोन वेनर ने बाल श्रम पर अपनी महत्वपूर्ण पुस्तक में
इंडिया15, भारत में बाल श्रम की समस्याओं को कमी से जोड़ता है

15 वेनर माइरोन (1991): द चाइल्ड एंड द स्टेट इन इंडिया इन कम्पेरेटिव पर्सपेक्टिव --

Machine Translated by Google

प्रारंभिक के क्षेत्र में पूर्व में प्रभावी उपाय

शिक्षा। इन संस्थाओं के पोषण के लिए बहुत सावधानी बरतनी चाहिए

क्योंकि हमारा भविष्य इन कक्षाओं में आकार लेता है। विक्टर ह्यूगो के पास था

प्रसिद्ध कहावत है 'जो स्कूल का दरवाजा खोलता है, वह जेल बंद करता है।'

बच्चे अभी भी खतरनाक वातावरण में काम कर रहे हैं और किशोर अभी भी खतरनाक वातावरण में काम कर रहे हैं

कानून के साथ टकराव, कुछ हद तक, की ओर इशारा करता है

हमारी प्रारंभिक शिक्षा प्रणाली में कमज़ोरी, दोनों पर

पहुंच और इसकी 'गुणवत्ता'।

एक शिक्षक के शैक्षणिक कौशल को बहुत ऊँचा स्थान दिया जाना चाहिए

प्राथमिकता। लेकिन हमारी प्राथमिकता अलग लगती है. यह प्रदान करना नहीं है

'गुणवत्तापूर्ण' शिक्षा, लेकिन बी.एड. को नौकरी के अधिक अवसर प्रदान करना।

प्रशिक्षित अभ्यर्थी, क्योंकि यही एकमात्र कारण प्रतीत होता है

समावेशन, प्रचुर सबूतों की उपस्थिति में कि बी.एड.

यह पाठ्यक्रम प्राथमिक कक्षाओं के लिए उपयुक्त पाठ्यक्रम नहीं है।

जो सामग्री इस न्यायालय के समक्ष रखी गई है

उच्चतम स्तर पर आधिकारिक संचार और बैठकों का स्वरूप

यह स्पष्ट करता है कि वर्तमान मामले में जो निर्णय लिया गया है

एनसीटीई किसी विशेषज्ञ निकाय का स्वतंत्र निर्णय नहीं है

क़ानून द्वारा बनाया गया और स्वतंत्र लेने का आदेश दिया गया

निर्णय. एनसीटीई का उद्देश्य के मानक में सुधार करना है

Machine Translated by Google

शिक्षा और रोजगार के और अवसर उपलब्ध नहीं कराना

बिस्तर। प्रशिक्षित शिक्षक. हम यह भी उल्लेख कर सकते हैं कि यह हो रहा है

तब किया जाएगा जब शिक्षकों को प्रारंभिक शिक्षा में प्रशिक्षित किया जा सकेगा

केवल प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक के रूप में कार्यरत हैं और कहीं नहीं

अन्यथा, जब बी.एड. से तुलना की जाती है। योग्य शिक्षक, जो हो सकता है

वरिष्ठ प्राथमिक कक्षाओं (छठी से आठवीं) में भी कार्यरत हैं

माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक कक्षाएँ। इसलिए यह किसी में भी है

डिप्लोमा धारकों के लिए मामला उचित नहीं, अब कौन देखेगा

उनके लिए उपलब्ध जगह और सिकुड़ती जा रही है।

बी.एड. का समावेश के द्वारा एक 'योग्यता' के रूप में किया गया था

अधिसूचना दिनांक 28.06.2018, जिसे पहले लागू किया गया था

राजस्थान उच्च न्यायालय. यह अधिसूचना नीचे पुन: प्रस्तुत की गई है:-

> “राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिसूचना नई दिल्ली, 28 जून,
> 2018 एफ. नं.
> एनसीटीई-Regl 012/16/2018- बच्चों के अधिकार की
> धारा 23 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा
> अधिनियम, 2009 (2009 का 35) एवं अधिसूचना क्रमांक एसपी के अनुसरण में
>
> 750(ई), दिनांक 31 मार्च, 2010, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास
> मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) इसके द्वारा
> अधिसूचना संख्या में निम्नलिखित और संशोधन करती है भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III,
> खंड 4, दिनांक 25 अगस्त, 2010 में प्रकाशित एफएन 61-03/20/2010/एनसीटीई/(एन एंड
> एस), दिनांक 23 अगस्त, 2010 को इसके बाद उक्त अधिसूचना के रूप में संदर्भित किया गया
> है। :-

Machine Translated by Google

(1) उक्त अधिसूचना में, पैरा 1 में उप-पैरा (i) में, खंड (ए) में शब्दों और कोष्ठक के बाद "स्नातक और प्रारंभिक शिक्षा में दो साल का डिप्लोमा (चाहे किसी भी नाम से जाना जाता है), निम्नलिखित डाला जाएगा , अर्थात्: - या "कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक और बैचलर ऑफ एजुकेशन (बी.एड.)"

2. उक्त अधिसूचना में पैरा 3 में, उप-पैरा (ए) के स्थान पर निम्नलिखित उप-पैरा प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(ए) जिसने बैचलर ऑफ की योग्यता हासिल कर ली है
कक्षा I से V तक शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए किसी भी NCTE मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा पर विचार किया जाएगा, बशर्ते कि शिक्षक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को अनिवार्य रूप से छह महीने का ब्रिज कोर्स करना होगा।

प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्ति के दो साल के भीतर एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त प्रारंभिक शिक्षा"

(जोर दिया गया)

30. घटनाओं का क्रम, जो अब अच्छी तरह से स्थापित हो चुका है

जो दस्तावेज राजस्थान हाई के समक्ष रखे गए थे

न्यायालय और इस न्यायालय के समक्ष, यह स्पष्ट करें कि निर्णय

बी.एड शामिल हैं। योग्यता के रूप में स्पष्ट रूप से एक द्वारा ट्रिगर किया गया था

KVS16 के आयुक्त का पत्र , जिन्होंने अनुरोध किया था

अनुरोध किया कि चूंकि केंद्रीय विद्यालयों की प्राथमिक कक्षाओं में

पर्याप्त संख्या में प्रशिक्षित डिप्लोमा धारक उपलब्ध नहीं हैं,

उन्हें बी.एड. नियुक्त करने की अनुमति दी जा सकती है। योग्य शिक्षक, जो

आसानी से उपलब्ध हैं. मंत्रालय ने इस पत्र का संज्ञान लिया है.

बैठकें आयोजित की जाती हैं और अंततः यह एनसीटीई को बी.एड. नियुक्त करने का निर्देश देता है।

16 केन्द्रीय विद्यालय संगठन - भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त निकाय, जो पूरे देश में केंद्रीय विद्यालयों के प्रबंधन की देखभाल करता है।

Machine Translated by Google

न केवल केंद्रीय विद्यालयों में बल्कि प्राथमिक विद्यालयों में भी प्रशिक्षित शिक्षक
पूरे देश में स्कूल, जिनमें राज्य द्वारा संचालित स्कूल भी शामिल होंगे
स्कूल. यह कैसे हुआ इसका क्रम इस प्रकार है।

दिनांक 28.05.2018 को मंत्रालय में एक बैठक आयोजित की गई
मानव संसाधन विकास मंत्री की अध्यक्षता में
संबंधित। बैठक में बीएड को मान्यता देने का निर्णय लिया गया. एक के रूप में
के पद पर नियुक्ति के लिए अतिरिक्त पात्रता मानदंड
केवीएस स्कूलों में प्राथमिक शिक्षक। इसके बाद एक नोट जारी किया गया
अगले ही दिन यानि 29.05.2018 को, जो कहता है कि चूंकि बी.एड.
योग्य उम्मीदवार प्राथमिक के रूप में नियुक्त होने के पात्र थे
केवीएस स्कूलों में शिक्षकों को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए
इस निर्देश को अन्य स्कूलों में भी लागू करें। इन
संचार दिनांक 30.05.2018 को जारी एक पत्र में समाप्त होता है
मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जो था
एनसीटीई अधिनियम की धारा 29 के तहत जारी एक निर्देश का प्रपत्र
जिसमें शामिल करने के लिए एनसीटीई को पात्रता मानदंड में संशोधन करने की आवश्यकता थी
बिस्तर। प्राथमिक शिक्षक के रूप में योग्य उम्मीदवार। इसके साथ अनुपालन
उपरोक्त निर्देशों के बाद, एनसीटीई ने विवादित अधिसूचना जारी की
28.06.2018.

Machine Translated by Google

दिनांक 28.05.2018 की बैठक के कार्यवृत्त से खुलासा

कारण कि बी.एड. योग्यता के रूप में शामिल किया जाना चाहिए।

ये मिनट्स निम्नानुसार बताते हैं:-

"....

2. इस मामले पर इस मंत्रालय में विचार किया गया और एचआरएम ने उच्च योग्यता (यानी बीए/बीएससी, बीएड+ टीईटी) के साथ प्राथमिक शिक्षक की भर्ती के लिए केवीएस के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा, एचआरएम ने यह भी निर्देश दिया है कि एनसीटीई योग्यता में संशोधन कर सकती है और बीए/बीएससी, बीएड कर सकती है। सेवा में शामिल होने के 2 वर्षों में शैक्षणिक मॉड्यूल पूरा करने के प्रावधान के साथ प्राथमिक स्तर पर शिक्षण के लिए भी पात्र, ये निर्देश 12.04.2018 को एनसीटीई को सूचित किए गए थे, हालांकि, उनके स्तर पर कार्रवाई अभी भी लंबित है।

3. एचआरएम की अध्यक्षता में आज (28 मई, 2018) हुई बैठक में इस मामले पर फिर से विस्तार से चर्चा की गई और विशेष सचिव, अध्यक्ष, एनसीटीई, एमएस, एनसीटीई, संयुक्त सचिव (एसई.आई) और केवीएस आयुक्त ने भाग लिया। केवीएस आयुक्त ने प्राथमिक शिक्षकों के पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की अपर्याप्त संख्या और देश भर के बजाय कुछ राज्यों से आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के मुद्दे उठाए। एमएस, एनसीटीई द्वारा बताया गया कि देश भर में डी.एल.एड के लिए लगभग 7.5 लाख सीटें उपलब्ध हैं, जिनमें से 50% सीटें भरी हुई हैं। हालाँकि, TET पास D.El.Ed. अभ्यर्थी काफी कम होंगे क्योंकि टीईटी का रिजल्ट 6% से 16% तक रहता है। इससे पात्र डी.एल.एड. की उपलब्धता हो जाती है। उम्मीदवार वांछित से काफी कम हैं।

एचआरएम ने स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए बेहतर सुसज्जित शिक्षकों की आवश्यकता भी बताई।
उच्च योग्यता वाले शिक्षकों की भर्ती अंततः लाभकारी और छात्रों के हित में होगी।

4. उपरोक्त के अलावा, एनसीटीई चार वर्षीय बी.एड. अगले शैक्षणिक वर्ष से एकीकृत पाठ्यक्रम, इसलिए प्रचलित D.El.Ed./B.Ed. आदि समयबद्ध तरीके से समाप्त हो जाएंगे। आगे इसी प्रकार का अनुरोध उत्तराखंड राज्य से भी किया गया है।

Machine Translated by Google

5. उपरोक्त चर्चाओं के मद्देनजर, एचआरएम ने एनसीटीई को अपने नियमों को बदलने का निर्देश दिया, एनसीटीई अधिनियम, 1993 की धारा 29 के तहत निर्देश दिए जाने की आवश्यकता है। एनसीटीई अधिनियम की धारा 29 इस प्रकार है: (1) परिषद इसमें शामिल होगी इस अधिनियम के तहत अपने कार्यों और कर्तव्यों का निर्वहन नीतिगत प्रश्नों पर ऐसे निर्देशों से बंधा होगा जो केंद्र सरकार उसे
समय-समय पर लिखित रूप में दे सकती है।

(2) कोई प्रश्न नीतिगत है या नहीं, इस पर केंद्र सरकार का निर्णय अंतिम होगा।

(6) हम एनसीटीई से अनुरोध कर सकते हैं कि वह जल्द से जल्द एनसीटीई नियमों में संशोधन के लिए मसौदा अधिसूचना प्रस्तुत करे। कृपया अनुमोदन हेतु प्रारूप पत्र संलग्न है। एक बार मसौदा अधिसूचना प्राप्त हो जाने के बाद, इसे एचआरएम की मंजूरी के साथ जांच के लिए विधायी विभाग को भेजा जाएगा।

प्रस्तुत।"

दिनांक 29.05.2018 की बैठक का विवरण इस प्रकार है

अंतर्गत :-

"नोट दिनांक 29.05.2018 कृपया एनसीटीई
के उस पत्र को फ़ाइल में रखें जो बैठक के दौरान एमएस, एनसीटीई द्वारा एचआरएम को सौंपा गया था, जिसका विवरण मसौदा उत्तर में संदर्भित किया गया है। बैठक में स्पष्ट रूप से निर्णय लिया गया कि आयुक्त, केवी द्वारा प्रस्तुत तथ्यों को ध्यान में रखते हुए और चूंकि एनसीटीई को केवी स्कूलों को उच्च योग्यता वाले प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती की अनुमति देने में कोई आपत्ति नहीं है, तो इसे अन्य स्कूलों तक विस्तारित करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। स्कूल, और इसलिए, यह मंत्रालय एनसीटीई को निर्देश जारी कर सकता है
धारा 29।"

सरकार की ओर से एनसीटीई को पत्र दिनांक 30.05.2018।

"पत्र दिनांक 30.05.2018

प्राथमिकता

Machine Translated by Google

F.No.11-15/2017-EE.10-भाग (1)
भारत सरकार मानव संसाधन
विकास मंत्रालय स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

शास्त्री भवन, नई दिल्ली,
दिनांक 30 मई, 2018

को,

अध्यक्ष एनसीटीई, हंस भवन, बहादुर
शाह जफर मार्ग, नई
दिल्ली - 110002।

प्रिय महोदया, कृपया

सम संख्या के पत्र का संदर्भ लें। उच्च योग्यता यानी बीए/बीएससी, बी.एड. वाले प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती के लिए केंद्रीय विद्यालय संगठन के अनुरोध के संबंध में दिनांक 12.04.2018। प्लस टीईटी पास और लेटर नंबर। एनसीटीई-आरईजी1012/16/2018- यूएस(विनियमन)-मुख्यालय दिनांक 23.05.2018 को एनसीटीई से इस संबंध में प्राप्त हुआ।

2. उपरोक्त अनुरोध पर इस मंत्रालय में विचार किया गया है। छात्रों के हितों की रक्षा करने और शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए, सक्षम प्राधिकारी ने उच्च योग्यता वाले प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती के लिए केवीएस के अनुरोध पर सहमति व्यक्त करने का निर्णय लिया है। पात्र D.EI.Ed की अपर्याप्त संख्या। प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती के लिए टीईटी परीक्षा का कम उत्तीर्ण प्रतिशत भी अभ्यर्थियों के लिए एक मुद्दा बन गया है। इसके अलावा, चार वर्षीय बी.एड. की शुरुआत के साथ। अगले शैक्षणिक वर्ष से एकीकृत पाठ्यक्रम, मौजूदा D.EI.Ed./B.Ed. समय के साथ पाठ्यक्रम चरणबद्ध तरीके से समाप्त कर दिए जाएंगे।

3. एनसीटीई ने क्रमांक एनसीटीई आरईजी1012/16/2018-यूएस (विनियमन)-मुख्यालय दिनांक 23.05.2018 के माध्यम से कहा कि "मानव संसाधन विकास मंत्री, भारत सरकार की विस्तृत नोटिंग में एमएचआरडी निर्देश को लागू करने पर विचार कर सकता है।" ”। आगे, तथ्यों को ध्यान में रखते हुए

Machine Translated by Google

आयुक्त, केवी द्वारा प्रस्तुत किया गया और चूंकि एनसीटीई को केवी स्कूलों को उच्च योग्यता वाले प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती की अनुमति देने में कोई आपत्ति नहीं थी, तो इसे अन्य स्कूलों में विस्तारित करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

इसलिए, एनसीटीई अधिनियम, 1993 की धारा 29 के तहत एमएचआरडी में निहित शक्तियों पर विचार करते हुए, एनसीटीई विनियमन 25.08.2010 (प्राथमिक स्तर कक्षा 1 से 5 वीं तक नियुक्त किए जाने वाले शिक्षक की योग्यता का निर्धारण) में संशोधन किया जाएगा ताकि किसी भी व्यक्ति को इसमें शामिल किया जा सके । बी.एड की योग्यता हासिल की। पहली से पांचवीं कक्षा में शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी पाठ्यक्रम पर भी विचार किया जाएगा, बशर्ते कि शिक्षक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक के रूप में नियुक्ति के दो साल के भीतर अनिवार्य रूप से 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना होगा, जो एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त है। अध्यापक।

4. इसलिए अनुरोध है कि एनसीटीई नियमों में संशोधन के लिए मसौदा अधिसूचना कृपया इस मंत्रालय को प्रस्तुत की जाए। कृपया इसे अत्यंत अत्यावश्यक माना जाए।

सस्नेह,

सादर,

एसडी/-
(Rashi Sharma)
निदेशक (टीई)"

इसके बाद दिनांक 28.06.2018 को अधिसूचना जारी की गई

एनसीटीई द्वारा, जिसका उल्लेख पहले ही ऊपर किया जा चुका है।

31. घटनाओं के क्रम से पता चलता है कि किस चीज़ की शुरुआत हुई थी

बीएड पर विचार के लिए कवायद योग्य उम्मीदवार जैसे

केंद्रीय विद्यालयों में प्राथमिक कक्षाओं के लिए शिक्षकों की संख्या का विस्तार किया गया

Machine Translated by Google

देश भर के सभी प्राथमिक विद्यालयों को शामिल करें।

स्पष्ट तर्क यह दिया गया है कि बी.एड. योग्य उम्मीदवार हैं

प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए बेहतर उपयुक्त है

उनके पास 'उच्च योग्यताएं' हैं, और ऐसी होनी भी चाहिए

सभी प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक नियुक्त किये गये। का एक और कारण

ऐसा करने से योग्य टीईटी अभ्यर्थियों की कमी है। आंकड़े

बैठक में दिए गए सुझावों से पता चलता है कि केवल 6% से 16%

टीईटी परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवार परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं।

सुझाव यह प्रतीत होता है कि बी.एड. को शामिल करने के साथ।

उम्मीदवारों की संख्या टीईटी उत्तीर्ण उम्मीदवारों की होगी

बढ़ोतरी। लेकिन यह तर्क तब सही नहीं बैठता जब बी.एड. के तौर पर

योग्यता ने बुनियादी शैक्षणिक सीमा को पार नहीं किया है

प्राथमिक कक्षाओं को पढ़ाना.

हम पहले ही इस पहलू की विस्तृत जांच कर चुके हैं। बिस्तर।

प्राथमिक स्तर की कक्षाओं में पढ़ाने के लिए कोई योग्यता नहीं है,

प्राइमरी के सन्दर्भ में, बेहतर या उच्च योग्यता तो बिल्कुल भी नहीं

कक्षाएं. यह निष्कर्ष एनसीटीई की स्वीकारोक्ति में स्वयं स्पष्ट है

जो अनिवार्य करता है कि सभी बी.एड. योग्य शिक्षक जो हैं

प्राथमिक स्तर की कक्षाओं को पढ़ाने के लिए अनिवार्य रूप से नियुक्त किया जाना चाहिए

दो के भीतर प्रारंभिक कक्षाओं के लिए एक शैक्षणिक पाठ्यक्रम से गुजरना

उनकी नियुक्ति के वर्ष.

Machine Translated by Google

32. सोसायटी फॉर अनएडेड प्राइवेट स्कूल्स ऑफ राजस्थान बनाम में।

भारत संघ एवं अन्य. (सुप्रा) इस न्यायालय ने कायम रखते हुए

आरटीई अधिनियम की वैधता, यह मानती है कि प्राथमिक शिक्षा, जो है

अब भाग III के तहत मौलिक अधिकार का एक हिस्सा है

संविधान, एक सार्थक शिक्षा होनी चाहिए, न कि केवल एक

औपचारिकता। जब प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा (D.El.Ed.), था

प्राथमिक में शिक्षकों के लिए एक आवश्यक योग्यता के रूप में रखा गया

स्कूल, यह एक उद्देश्य के साथ था, और उद्देश्य घोषित करना था

केवल ऐसे शिक्षक ही योग्य हैं जो शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रशिक्षित हैं

'प्राथमिक स्तर' पर बच्चों को शिक्षा। एक बच्चे के लिए शिक्षाशास्त्र

जिसने अभी-अभी स्कूल में प्रवेश किया है, यह एक महत्वपूर्ण विचार है। ए

बच्चे को पहली बार किसी "शिक्षक" का सामना करना पड़ा है

एक कक्षा में। यह बच्चे के लिए एक यात्रा की शुरुआत है

विद्यार्थी और इसलिए दुनिया भर में बिछाने में बहुत सावधानी बरती जाती है

इन प्रारंभिक वर्षों में उचित नींव तैयार करें। अच्छी तरह से योग्य

और प्राथमिक विद्यालय में प्रशिक्षित शिक्षक अत्यंत महत्वपूर्ण है

पहलू। एक शिक्षक को "प्राथमिक" स्तर पर छात्रों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए

स्तर", और यही डिप्लोमा का प्रशिक्षण है

प्रारंभिक शिक्षा (D.El.Ed.) करता है; यह एक व्यक्ति को सिखाने के लिए प्रशिक्षित करता है

प्राथमिक स्तर के बच्चे. बिस्तर। 'उच्च योग्यता' नहीं है, या a

बेहतर योग्यता, जैसा कि इसके पक्ष में प्रचारित किया जा रहा है

Machine Translated by Google

इसकी तुलना 'डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन' से की जा रही है। बिस्तर। एक है

भिन्न योग्यता; एक अलग प्रशिक्षण. यह मानते हुए भी कि यह एक है

उच्च योग्यता, फिर भी यह उपयुक्त योग्यता नहीं होगी

प्राथमिक स्तर की कक्षाओं के लिए. प्रारंभिक में डिप्लोमा के विपरीत

शिक्षा (डी.एल.एड.), बी.एड. किसी शिक्षक को पढ़ाने के लिए तैयार नहीं करता

प्राथमिक स्तर। अधिसूचना में इस तथ्य को स्पष्ट रूप से मान्यता दी गई है

साथ ही (अधिसूचना दिनांक 28.06.2018), जिसके लिए अभी भी आवश्यकता है

व्यक्ति, जो बी.एड. के साथ शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। के लिए योग्यता

'अनिवार्य रूप से प्राथमिक में छह महीने का ब्रिज कोर्स करना होगा

शिक्षा'। यह बी.एड. को शामिल करने के तर्क को ही खारिज कर देता है। के तौर पर

योग्यता, वही अधिसूचना है जो इसके लिए प्रेरित करती है

बी.एड. को शामिल करने से इसके अंतर्निहित शैक्षणिक को भी मान्यता मिलती है

प्राथमिक कक्षाओं के संबंध में कमजोरी। इसे कवर करना है

दोष, कि ऐसे सभी उम्मीदवारों को अनिवार्य छह से गुजरना होगा

प्रारंभिक शिक्षा में महीनों का ब्रिज कोर्स! यहाँ विडम्बना है

क्या यह सब तब किया जा रहा है जब राजस्थान राज्य पहले से ही है

डिप्लोमा उत्तीर्ण करने वालों की संख्या आवश्यक संख्या से अधिक है

उम्मीदवार उपलब्ध हैं. यह इस तथ्य के अलावा है कि वहाँ है

वर्तमान में ऐसा कोई "ब्रिज कोर्स" उपलब्ध नहीं है; कम से कम वहाँ था

राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा याचिका के निस्तारण तक कोई नहीं।

Machine Translated by Google

33. इन परिस्थितियों में हम समझ नहीं पाते

बी.एड. को शामिल करने की अत्यधिक आवश्यकता क्या थी? उम्मीदवार,

जो निश्चित रूप से प्राथमिक कक्षाएँ लेने के लिए पूरी तरह से प्रशिक्षित नहीं हैं!

नतीजतन, एनसीटीई ने बीएड को शामिल करने का निर्णय लिया। के तौर पर

प्राथमिक विद्यालय में शिक्षकों की योग्यता मनमानी लगती है,

अनुचित है और वास्तव में इसका इच्छित उद्देश्य से कोई संबंध नहीं है

अधिनियम अर्थात शिक्षा का अधिकार अधिनियम द्वारा प्राप्त किया जाना है, जो देना है

बच्चों को न केवल निःशुल्क एवं अनिवार्य बल्कि 'गुणवत्तापूर्ण' भी

शिक्षा।

34. इसलिए हमारी सुविचारित राय में एनसीटीई उचित नहीं था

जिसमें बी.एड. पद पर नियुक्ति के लिए योग्यता के रूप में

प्राथमिक विद्यालय शिक्षक (स्तर-1) की योग्यता, यह अब तक थी

जानबूझकर पात्रता की आवश्यकता से बाहर रखा गया। राजस्थान

उच्च न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय के माध्यम से सही प्रहार किया था

दिनांक 28.06.2018 की अधिसूचना निम्नलिखित पर अंकित करें

आधार:-

"(i) दिनांक 28.06.2018 की लागू अधिसूचना गैरकानूनी है क्योंकि: -

(ए) यह केंद्र सरकार के निर्देशन में है, जो आरटीई अधिनियम की धारा 23 की उपधारा (1) के तहत केंद्र सरकार के पास नहीं है; और

(बी) यह केंद्र की शक्ति का प्रयोग नहीं है
सरकार आरटीई की धारा 23 की उपधारा (2) के तहत

Machine Translated by Google

अधिनियम एनसीटीई द्वारा निर्धारित पात्रता मानदंडों को शिथिल करता है, न ही ऐसी शक्ति का प्रयोग करने के लिए पूर्ववर्ती शर्तों के अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए कोई अभ्यास किया गया है।

(ii) याचिकाकर्ताओं के पास दिनांक 28.06.2018 की अधिसूचना को चुनौती देने का अधिकार है। केवल इसलिए कि एक अतिरिक्त योग्यता को पात्रता मानदंडों में से एक के रूप में मान्यता दी गई है, याचिकाकर्ताओं को इसे चुनौती देने से नहीं रोका जा सकता है।

(iii) बी.एड. वाले उम्मीदवार को स्वीकार करना। नियुक्ति के लिए पात्र के रूप में डिग्री और उसके बाद उसे नियुक्ति के दो साल के भीतर ब्रिज कोर्स पूरा करने के लिए बाध्य करना मौजूदा पात्रता मानदंडों में ढील देने की प्रकृति में है, जिसे केंद्र सरकार केवल धारा 23 और विषय की उप-धारा (2) के भीतर ही कर सकती थी। ऐसी शक्ति के प्रयोग के लिए आवश्यक परिस्थितियों का अस्तित्व।

(iv) राज्य सरकार आरईईटी के लिए विज्ञापन जारी करते समय एनसीटीई की दिनांक 28.06.2018 की अधिसूचना को नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। हालाँकि, जब हमने घोषित कर दिया है कि यह अधिसूचना अवैध है और रद्द करने की प्रक्रिया में हैं, तो मुद्दा अकादमिक महत्व का हो जाता है।

35. वर्तमान मामले का एक महत्वपूर्ण पहलू अब निपटाया जाना चाहिए

के साथ, जिस पर वकील द्वारा बहुत जोर दिया गया था

अपीलकर्ता निवेदन यह है कि केंद्र सरकार किसी भी तरह से

मामला यह तय करने वाला अंतिम प्राधिकारी है कि उसके पास क्या योग्यता है

शिक्षकों के लिए वहां मौजूद रहना और एनसीटीई इसका पालन करने के लिए बाध्य है

इस संबंध में केंद्र सरकार के निर्देश. रिलायंस था

राष्ट्रीय शिक्षक परिषद के दो प्रावधानों पर रखा गया

शिक्षा अधिनियम, (एनसीटीई अधिनियम), धारा 12ए और धारा 29। हमें अवश्य करना चाहिए

Machine Translated by Google

प्रस्तुत प्रस्तुतियों के आलोक में इन प्रावधानों की जांच करें

हमारे सामने।

अधिनियम की धारा 12ए इस प्रकार है:

"12ए. स्कूली शिक्षकों की शिक्षा के न्यूनतम मानक निर्धारित करने की परिषद की शक्ति। - स्कूलों में शिक्षा के मानकों को बनाए रखने के उद्देश्य से, परिषद, विनियमों द्वारा, किसी भी पूर्व-प्राथमिक, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, वरिष्ठ माध्यमिक या इंटरमीडिएट स्कूल या कॉलेज में शिक्षक के रूप में भर्ती होने के लिए व्यक्तियों की योग्यता निर्धारित कर सकती है। , केंद्र सरकार या राज्य सरकार या स्थानीय या अन्य प्राधिकारी द्वारा किसी भी नाम से जाना जाता हो, स्थापित किया गया हो, चलाया जाता हो, सहायता प्राप्त हो या मान्यता प्राप्त हो:

बशर्ते कि इस धारा की कोई भी बात केंद्र द्वारा बनाए गए किसी भी नियम, विनियमन या आदेश के तहत किसी भी पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, वरिष्ठ माध्यमिक या मध्यवर्ती स्कूलों या कॉलेजों में भर्ती किए गए किसी भी व्यक्ति की निरंतरता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी।

सरकार, एक राज्य सरकार, एक स्थानीय या अन्य प्राधिकरण, के शुरू होने से ठीक पहले

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (संशोधन) अधिनियम, 2011 (2011 का 18) केवल ऐसी योग्यताओं को पूरा न करने के आधार पर जैसा कि द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है

परिषद:

बशर्ते कि पहले परंतुक में निर्दिष्ट शिक्षक की न्यूनतम योग्यता इस अधिनियम में निर्दिष्ट अवधि के भीतर या बच्चों के मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (2009 का 35) के तहत हासिल की जाएगी।]"

इसके बाद एनसीटीई एक्ट में धारा 12ए जोड़ी गई

शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 का अधिनियमन। केवल धारा 12ए

Machine Translated by Google

शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 23 की सराहना करते हैं, जिसे हम

पिछले पैराग्राफ में पहले ही चर्चा की जा चुकी है।

इसके बाद, हम एनसीटीई अधिनियम की धारा 29 पर आते हैं जो इस प्रकार है

अंतर्गत:

> "29. केंद्र सरकार द्वारा निर्देश: (1) परिषद, इस अधिनियम के तहत अपने कार्यों और कर्तव्यों के निर्वहन में नीति के प्रश्नों पर ऐसे निर्देशों से बंधी होगी जो केंद्र सरकार उसे समय-समय पर लिखित रूप में दे सकती है।
>
> (2) कोई प्रश्न नीतिगत है या नहीं, इस पर केंद्र सरकार का निर्णय अंतिम होगा।

यह प्रस्तुत किया गया कि दिनांक 28.06.2018 की एक अधिसूचना द्वारा,

एनसीटीई ने सिर्फ केंद्र सरकार के निर्देशों का पालन किया है

जो एक नीति की प्रकृति में हैं। इसके अलावा यह और भी स्पष्ट है

दिनांक 28.05.2018 की बैठक का कार्यवृत्त जहां था

स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार का निर्देश शामिल है

बिस्तर। योग्यता के रूप में अधिनियम की धारा 29 के तहत एक निर्देश है।

एनसीटीई केंद्र के निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य है

इस संबंध में सरकार और वर्तमान मामले में दिशा

बी.एड को शामिल करना था। प्राथमिक में शिक्षकों के लिए योग्यता के रूप में

स्कूल, जो एनसीटीई द्वारा अधिसूचना दिनांक के माध्यम से किया गया है

28.06.2018, के लिए विद्वान वकील की दलीलें हैं

अपीलकर्ताओं के साथ-साथ विद्वान एएसजी सुश्री ऐश्वर्या की भी

Machine Translated by Google

भारत संघ की ओर से भाटी। इसके अलावा, उप के अनुसार

धारा 29 की धारा (2) केंद्र सरकार का निर्णय

नीतिगत निर्णय अंततः क्या मायने रखता है, यह मायने रखता है

तर्क भी.

36. बी.एड. की शुरूआत. एनसीटीई द्वारा योग्यता के रूप में

केंद्र सरकार का निर्देश एक नीतिगत निर्णय है

सरकार, जैसा कि इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, और है भी

घटनाओं के अनुक्रम, विभिन्न विवरणों से स्पष्ट है

बैठक कर इस संबंध में आदेश पारित किया गया. एनसीटीई की धारा 29

अधिनियम जो कहता है कि एनसीटीई को निर्देशों का पालन करना चाहिए

केंद्र सरकार अपने कार्यों का निर्वहन कर रही है। यह एक नीति है

निर्णय जो एनसीटीई को बाध्य करता है।

हमारे मन में उस नीति पर बिल्कुल कोई संदेह नहीं है

सरकार के निर्णयों में सामान्यतः हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए

एक संवैधानिक न्यायालय द्वारा अपनी न्यायिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए

समीक्षा। साथ ही यदि नीतिगत निर्णय ही इसके विपरीत हो

यह कानून मनमाना और तर्कहीन है, न्यायिक समीक्षा की शक्तियाँ

व्यायाम करना चाहिए.

एक नीतिगत निर्णय जो पूरी तरह से मनमाना है; के विपरीत

कानून, या कोई निर्णय जो उचित के बिना लिया गया हो

दिमाग का प्रयोग, या प्रासंगिक कारकों की पूर्ण उपेक्षा है

Machine Translated by Google

इसमें हस्तक्षेप किया जा सकता है, क्योंकि यह कानून का आदेश भी है

संविधान। इस पहलू को इस न्यायालय द्वारा दोहराया गया है

बार बार।

जहाँ कोई हो वहाँ न्यायिक समीक्षा आवश्यक हो जाती है

अवैधता, अतार्किकता या प्रक्रियात्मक अनौचित्य। ये सिद्धांत

काउंसिल ऑफ सिविल सर्विस में लॉर्ड डिप्लॉक द्वारा प्रकाश डाला गया था

यूनियन बनाम सिविल सेवा मंत्री17 (आमतौर पर के रूप में जाना जाता है

सीसीएसयू मामला)। उपरोक्त निर्णय इस न्यायालय द्वारा संदर्भित किया गया है

दिल्ली एनसीटी राज्य बनाम संजीव18 में। इस विचार को दोहराया गया

फिर से इस न्यायालय द्वारा मप्र राज्य एवं अन्य में। वि. माला बनर्जी19 :-

> "6. हम स्वयं को अपीलकर्ताओं की इस दलील से सहमत होने में भी असमर्थ पाते हैं कि यह एक नीतिगत मामला है और इसलिए, इसमें अदालतों द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। फेडरेशन ऑफ रेलवे ऑफिसर्स एसोसिएशन में । बनाम भारत संघ [(2003) 4 एससीसी 289], इस न्यायालय ने पहले ही न्यायिक समीक्षा के दायरे पर विचार किया है और गणना की है कि जहां कोई नीति कानून के विपरीत है या संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन है या मनमाना या तर्कहीन है , अदालतों को इसे ख़त्म करके अपने संवैधानिक कर्तव्यों का पालन करना चाहिए..."

17 (1984) 3 सभी ईआर 935 : 1985 एसी 374 : (1984) 3 डब्लूएलआर 1174 (एचएल)

18 (2005) 5 एससीसी 181

19 (2015) 7 एससीसी 698

Machine Translated by Google

बृज मोहन लाल बनाम भारत संघ20 में न्यायालय ने इस बात को दोहराया

इस पहलू पर और जहां एक के रूप में एक भेद बनाया

किसी निर्णय में हस्तक्षेप आवश्यक है, और जबकि यह नहीं है:-

> "100. कुछ परीक्षण, कि क्या इस न्यायालय को राज्य के नीतिगत निर्णयों में हस्तक्षेप करना चाहिए या नहीं, जैसा कि अन्य निर्णयों में कहा गया है, को इस प्रकार संक्षेपित किया जा सकता है:
>
> (मैं) यदि नीति तर्कसंगतता की कसौटी पर खरी नहीं उतरती तो यह असंवैधानिक होगी।
>
> (II) नीति में बदलाव निष्पक्ष रूप से किया जाना चाहिए और ऐसा आभास नहीं होना चाहिए कि यह किसी गलत इरादे से मनमाने ढंग से किया गया है।
>
> (III) नीति दुर्भावना, अनुचितता, मनमानी या अनुचितता आदि के आधार पर दोषपूर्ण हो सकती है।
>
> (IV) यदि नीति किसी क़ानून या संविधान के विरुद्ध पाई जाती है या इन प्रावधानों के पीछे के दर्शन के विपरीत चलती है।
>
> (V) यह अधिनियम या विधान के प्रावधानों का उल्लंघन करता है।
>
> (VI) यदि प्रतिनिधि ने प्रतिनिधिमंडल की अपनी शक्ति से परे कार्य किया है।
>
> 101. इस प्रकृति के मामलों को दो मुख्य वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है: एक वर्ग है

---

20 (2012) 6 एससीसी 502

Machine Translated by Google

राज्य के सामान्य नीतिगत निर्णयों से संबंधित मामले और दूसरे राज्य की राजकोषीय नीतियों से संबंधित मामले। पूर्व श्रेणी के मामलों में, जब कार्य मनमाने ढंग से, दुर्भावनापूर्ण या देश के कानून के विपरीत होते हैं तो अदालतों ने न्यायिक समीक्षा के दायरे का विस्तार किया है; जबकि बाद के वर्ग के मामलों में, ऐसी न्यायिक समीक्षा का दायरा बहुत संकीर्ण है।

फिर भी, अनुचितता, मनमानी, अनुचित कार्य या कानून के अक्षर, इरादे और दर्शन के विपरीत नीतियां और प्रत्यायोजित शक्ति की अनुमेय सीमा से परे विस्तार करने वाली नीतियां ऐसे उदाहरण होंगे जहां अदालतें सरकारी नीति में हस्तक्षेप करने के लिए कदम उठाएंगी।

बीएड को शामिल करने या बाहर करने का निर्णय के तौर पर

प्राथमिक विद्यालय में शिक्षकों के लिए योग्यता शैक्षणिक है

निर्णय, जिसे उचित अध्ययन के बाद लिया जाना है

शैक्षणिक निकाय यानी एनसीटीई और इसे इस विशेषज्ञ पर छोड़ देना बेहतर होगा

शरीर।

लेकिन जैसा कि हमने बीएड को शामिल करने का निर्णय देखा है। के तौर पर

योग्यता एनसीटीई का स्वतंत्र निर्णय नहीं है, लेकिन था

केंद्र सरकार और एनसीटीई का फैसला सरल था

धारा 29 के तहत एक निर्देश होने के नाते इसे पूरा करने का निर्देश दिया

एनसीटीई अधिनियम के अनुसार, एनसीटीई ने एक निर्देश का पालन किया।

वर्तमान मामले में और मामले के व्यापक संदर्भ में,

हम इसे नीतिगत निर्णय के रूप में भी नहीं देख सकते। लेकिन बिना मिले

Machine Translated by Google

इस तर्क में, यहाँ तक कि तर्क के लिए मान भी लिया

शासन स्तर पर बीएड को शामिल करने का निर्णय लिया गया। के तौर पर

प्राथमिक स्तर पर शिक्षकों के लिए योग्यता एक नीतिगत निर्णय है, हम

कहना होगा कि यह निर्णय सही नहीं है क्योंकि यह इसके विपरीत है

अधिनियम का उद्देश्य. वास्तव में, यह इसकी मूल भावना के विपरीत है

संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकार

अनुच्छेद 21ए. यह अधिनियम के विशिष्ट अधिदेश के विरुद्ध है, जो

निःशुल्क, अनिवार्य और सार्थक प्राथमिक शिक्षा का आह्वान

बच्चे। बी.एड. को शामिल करके। शिक्षकों के लिए योग्यता के रूप में

प्राइमरी स्कूल के खिलाफ केंद्र सरकार ने कार्रवाई की है

संविधान और कानूनों के प्रावधान। एक ही तर्क दिया गया

केंद्र सरकार द्वारा बी.एड. जैसी योग्यता है

कि यह एक 'उच्च योग्यता' है. यह हम पहले ही देख चुके हैं कि ऐसा नहीं है

सही। इन परिस्थितियों में हमें यह कहने में कोई झिझक नहीं है

अधिसूचना को सही ढंग से रद्द कर दिया गया है और निर्णय लिया गया है

राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ को बरकरार रखना होगा।

हमारी सुविचारित राय में इसलिए की दिशा

केंद्र सरकार दिनांक 30.05.2018 में समापन

एनसीटीई की अधिसूचना दिनांक 28.06.2018 का उल्लंघन है

आरटीई अधिनियम में निर्धारित सिद्धांत। इतना ही नहीं नोटिफिकेशन

Machine Translated by Google

यह कानून के उद्देश्य और आदेश के विपरीत है, जो कि है

बच्चों को सार्थक और 'गुणवत्तापूर्ण' प्राथमिक शिक्षा प्रदान करें।

पूरी प्रक्रिया प्रक्रियात्मक रूप से भी त्रुटिपूर्ण है।

अधिसूचना दिनांक 28.06.2018 का स्वतंत्र निर्णय नहीं है

एनसीटीई ने काफी विचार-विमर्श के बाद यह निर्णय लिया, लेकिन वह केवल इसका पालन करती है

केंद्र सरकार का निर्देश, एक ऐसा निर्देश जो विफल रहता है

दिन की वस्तुगत वास्तविकताओं को ध्यान में रखें।

उपरोक्त निश्चय करने के बाद हम सभी एक समान हैं

यह भी माना जाता है कि राजस्थान राज्य था

बीएड से आवेदन न मंगाना स्पष्ट रूप से त्रुटिपूर्ण है। योग्य

अभ्यर्थी, इस कारण से कि उस समय तक जब ऐसा हो

राजस्थान सरकार द्वारा बी.एड. का विज्ञापन जारी किया गया था।

के अनुसार अभ्यर्थियों को योग्य अभ्यर्थियों के रूप में शामिल किया गया

एनसीटीई की वैधानिक अधिसूचना, जो बाध्यकारी थी

राजस्थान सरकार, तक इसे अवैध या घोषित कर दिया गया

न्यायालय द्वारा असंवैधानिक. राजस्थान उच्च न्यायालय ने किया था

ठीक ही निम्नानुसार देखा गया है:-

> “..हमारी राय है कि राज्य सरकार आरईईटी के लिए आवेदन आमंत्रित करते समय अधिसूचना को नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। भले ही राज्य सरकार की राय हो कि ऐसी अधिसूचना असंवैधानिक या किसी भी कारण से अवैध थी

Machine Translated by Google

उसी पर रोक लगानी होगी या अलग रखनी होगी
इससे पहले कि सक्षम अदालत इसे नज़रअंदाज कर दे।"
[आक्षेपित निर्णय का पैरा 45]

राजस्थान उच्च न्यायालय ने ऊपर जो कहा था वह यही है

तय कानूनी स्थिति. हाल ही में तीन जजों के एक फैसले में यह

मणिपुर राज्य और अन्य में न्यायालय । वी. सुरजाकुमार ओकराम और

अन्य. [21] यह स्थिति यह है कि एक क़ानून जो एक सक्षम व्यक्ति द्वारा बनाया जाता है

विधायिका तब तक वैध है जब तक इसे न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित नहीं कर दिया जाता

कानून की; दोहराया गया है.

37. परिणामस्वरूप, अपीलें खारिज की जाती हैं और निर्णय सुनाया जाता है

राजस्थान उच्च न्यायालय की दिनांक 25.11.2021 को बरकरार रखा गया है।

अधिसूचना दिनांक 28.06.2018 को रद्द कर दिया गया है और रद्द कर दिया गया है।

रिट याचिकाएं और सभी लंबित आवेदनों का निपटारा किया जाता है

उपरोक्त आदेश के आलोक में.

.....जे।
[अनिरुद्ध बोस]

.....जे।
[SUDHANSHU DHULIA]

नई दिल्ली
11 अगस्त 2023.

21 2022 एससीसी ऑनलाइन एससी 130